Development of National and International Airports

*24. PROF. M.M. AGARWAL: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the details of ongoing projects for development of various airports, both national and international, in the country; and

(b) the details of target set for commissioning the aforesaid airports?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI PRAFUL PATEL): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Modernisation and upgradation of airports is a continuous process and is taken up depending upon traffic requirements, availability of funds, economic viability, availability of lands, and social considerations etc.

Various categories of development works being undertaken at national and international airports include runways, taxiways, apron, technical buildings, ground lighting facilities, Communication and Navigational aids (CNS) etc. These works are being executed in 52 airports at the total cost of Rs. 886.96 crores. These works are at various stages of implementation.

प्रो. एम.एम. अग्रवाल: आदरणीय सभापति जी, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन वेग तरीके से दिया है। उन्होंने इसमें लिखा है कि 52 एयरपोर्ट्स का हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं। मंत्री जी ने यह नहीं बताया है कि 52 एयरपोर्ट्स कौन से हैं? मंत्री जी, कम से कम दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर, कोलकाता एयरपोर्ट्स के बारे में तो बतायें कि इनमें क्या-क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं और इनमें क्या-क्या विकास हुआ है? मेरी जानकारी में अब तक तो कोई विकास नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि सिक्योरिटी के लिहाज से सरकार ने क्या विकास किया है?

श्री प्रफुल्ल पटेल: सभापति जी, माननीय सदस्य ने 52 हवाई अड्डों की बात कही है। अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से उनको जानकारी प्रेषित करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन्होंने कुछ बड़े हवाई अड्डों की बात यहां पर कही है। सर, यह तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। जिन-जिन हवाई अड्डों का विकास होता है, विस्तार होता है, वह उनकी जरुरतों के आधार पर होता है। यदि माननीय सदस्य मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहते हैं तो मैं उनको निश्चित रूप से देने के लिए तैयार हूं।

प्रो. एम.एम. अग्रवाल: सर, मेरा सेकेंड सप्लीमेंट्री प्रश्न यह है कि 22 अप्रैल, 2003 में स्टार्ड क्वेश्चन नम्बर 474 में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि कानपुर, जो कि एक औद्योगिक नगर है,

उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर है, मंत्री जी उसके लिए कब तक हवाई सेवा प्रदान करेंगे। सभापति महोदय, आपके माध्यम से पिछले मंत्री जी ने कहा था कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं और कानपुर को हवाई सेवा प्रदान करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये कब तक कानपुर में हवाई सेवायें प्रदान करेंगे?

श्री प्रफुल्ल पटेल: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कानपुर के बारे में जो बाते कही हैं, उनके बारे में पिछले मंत्री ने क्या कहा और मैं क्या कह रहा हूं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह मामला निश्चित तौर पर विचाराधीन है और हमारे मंत्रालय में इसके बारे में शीघ्र ही निर्णय लिया जाने वाला है।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, it is well known that our international airports are a shame and a disgrace. When one comes in, for example, from Kuala Lumpur, or from Singapore, or from Dubai, or from Bangkok, one can see the sharp difference. I know some people who have landed at the so-called Indira Gandhi International Airport and could not believe that it is an international airport. In a great country like India, we do not have one international-level airport, air terminal building.

Sir, 30 years ago, when I was the Minister for Aviation, I had involved Buckminster Fuller, a great futuristic thinker, as our consultant, for a new theory of airports. Thirty years have elapsed, plans were made, and we are still functioning out of those outmoded, upgraded barracks. The Palam Airport was just a barrack—an air force barrack. Would the hon. Minister be pleased to tell the House what steps he is going to take, at least, to give us decent international-level airports at our four metropolitan cities, and when will that be done?

श्री प्रफुल्ल पटेल: माननीय सभापति महोदय, डा॰ कर्ण सिंह जी पहले इस मंत्रालय के मंत्री भी रह चुके हैं और उनको काफी अनुभव है। माननीय सदस्य महोदय ने यहां पर जो कुछ सूचना दी है और जो टिपण्णी की है, यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए कुछ और विशेषकर हमारे मंत्रालय के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से मुम्बई, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए कुछ हमारी योजना रीस्ट्रैक्चरिंग और माडर्नाइजेशन की है और उस योजना के तहत हम मुम्बई और दिल्ली एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर अपग्रेड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए हैं। हमने मुम्बई और दिल्ली के एयरपोर्ट के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप आफ मिनिस्टर्स भी गठित किया है ताकि इस कार्यवाही को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जा सके।

श्री अहमद पटेल: माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सूरत जैसा कि सभी जानते हैं, न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण

शहर है। वहां एयरपोर्ट का रीस्ट्रक्चरिंग और माडर्नाइजेशन का जो काम चल रहा है या सैंक्शन हुआ है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है।

श्री प्रफुल्ल पटेल: महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूरत की बात कही है, सूरत निश्चित तौर पर हमारे देश की एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है, जहां से विशेषकर एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में होता है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि अगले ही कुछ दस-पन्द्रह दिनों के भीतर एक नई हवाई सेवा और पहली हवाई सेवा सूरत के लिए रेग्युलर शुरू करने की योजना एक प्राइवेट कैरियर के माध्यम से हो रही है। सूरत एयरपोर्ट के लिए जो कुछ इनफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थीं रन-वे की, अन्य जो उसके नेविगेशनल ऐड्ज़ और बाकी सब चीज़ें लगती हैं, उन सारी चीज़ों की करीब-करीब पूर्ति हो चुकी है और शीघ्र ही मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि इसी महीने में वहां पर ...(व्यवधान)... हमारे साथी कह रहे हैं कि भोपाल और इन्दौर के बारे में सोचें तो निश्चित ही भोपाल और इन्दौर भी हमारे नज़रिए में, ये दोनों सेंटर्स हैं और इनके अपग्रेडेशन के लिए, मॉडर्नाइज़ेशन के लिए और मध्य प्रदेश को कम से कम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिले, इसके लिए भी हमारे मंत्रालय में प्रस्ताव विचाराधीन है।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, as is very correctly pointed out by the Minister, modernisation and upgradation of all airports is a continuous process, I would like to put specific questions about modernisation and renovation of Delhi and Mumbai airports. (a) Is it not a fact that from 1993, and from 1996, onwards, so far as Mumbai and Delhi airports are concerned, there were specific programmes of renovation and modernisation put up by the Airports Authority to the Government? (b) Is it not a fact that despite all these programmes, all this planning, modernisation and upgradation of airports, or whatever scheme was given, works were being stalled, at one stage or another, for some reason or the other? (c) In the last Report on the Demands for Grants, placed in this House by the Standing Committee, it was specifically pointed out that the Ministry had put on hold even some of the major renovation jobs in these airports on the plea of leasing or privatisation. I want to know whether, based on those recommendations, people who are responsible for stalling these ongoing modernisation or renovation activities would be held accountable and whether an inquiry would be made as to why these delays had occurred in the development of airports and why this modernisation or upgradation work was held up for years together by certain people in the earlier Government, specifically concerning these two airports.

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, I still repeat that modernisation and upgradation of all airports, including Mumbai and Delhi, is a continuous process. Since 1993, there has been considerable amount of investment made in both Mumbai and Delhi airports. Therefore, it is not very specifically clear as to what activity the hon. Member is referring to because new additional terminals have been made in Mumbai. They have been upgraded, both in Mumbai and Delhi.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, there was a comprehensive scheme...

MR. CHAIRMAN: Mr. Mukherjee, let him speak.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I can say about Delhi Airport; it was Rs. 771 crores. That was the scheme...*(Interruptions)*...

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, I will definitely take the sentiments of the hon. Member into account, and will really find out as to what exactly has not happened, as per what he has discussed over here.

श्री दत्ता मेघे: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जब हवाई अड्डों की बात हो रही है तो नागपुर एयरपोर्ट में कारगो हब बनाने के बारे में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपके विभाग को लेटर भी लिख रही है और पिछली गवर्नमेंट ने कहा था कि हम करेंगे। इंटरनेशनल कारगो हब में आप नागपुर में खर्चा करेंगे तो उसका बहुत फायदा आपके विभाग को होने वाला है। आप उस एरिया से आते हैं, उस एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो कम से कम जो पेंडिंग है और जो विभाग के ख्याल में है, तो उसके बारे में आप कुछ ऐसा करें ताकि उन लोगों को भी फायदा मिले। पुरानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तीन बार आपके विभाग को पत्र लिखा है तो बताएं कि नागपुर के कारगो हब के बारे में आप क्या करना चाहते हैं।

श्री सभापति: कह दीजिए कि विचाराधीन है।

श्री प्रफुल्ल पटेल: माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...क्योंकि अब यह हमारा ही मामला है इसलिए पहले घर को तो देखना ही पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि यह योजना नागपुर को इन्टरनेशनल कारगो हब बनाने के लिए है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से इसमें काफी प्रगति हुई है; इस दिशा में उनके ओर प्रयत्न जारी हैं। पिछले कुछ दिनों पूर्व ही हमने यहां दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में महाराष्ट्र के सभी अधिकारी और हमारा मंत्रालय उसमें शामिल हुआ था। नागपुर की इस योजना को गति देने के लिए हमने सारी जानकारी प्राप्त की है। एमएडीसी नागपुर में जो हवाई अड्डा है, उसको महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल परपज व्हीकल के लिए स्टेब्लिश किया है और उसके माध्यम से एयर पोर्ट का डेवलेपमेंट होने जा रहा है। इसमें जो भी आवश्यकता उनको होगी वह

केन्द्र सरकार की ओर से पूरी होगी। चूंकि नागपुर देश के मध्य में है। इससे चारों ओर आसानी से आवागमन हो सकता है, आना जाना हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि नागपुर पैसेंजर और कारगो दोनों का एक हब बने।

श्री सभापति: क्या आप कोई डेफिनेट बात कह सकते हैं?

श्री प्रफुल्ल पटेल: माननीय सदस्य महोदय से मैं यह कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कारगो हब के बारे में...

श्री सभापति: चलो छोड़ो।

श्री प्रफुल्ल पटेल: आपने जो बात रखी है, महाराष्ट्र सरकार जो बात कहती आ रही है, यह टॉप प्रायोरिटी पर हमारे मंत्रालय में है।

Nationalisation of Rural Banks

*25. SHRIMATI JAMANA DEVI BARUPAL†:
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether rural bank employees have asked the Central Government to nationalize rural banks with a view to effectively increasing rural credit in villages and to save farmers from the debt trap;

(b) whether rural banks were promoted with an aim to support small and marginal farmers and artisans in villages and were made to extend credit to affluent customers under the supervision of commercial banks;

(c) if so, whether Government have considered their suggestions; and

(d) if so, what steps are being taken to improve rural banking in the country?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Employees Associations/Unions of Regional Rural Banks have been suggesting the following for restructuring/reorganization of Regional Rural Banks (RRBs).

(i) Recapitalisation of RRBs:

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Jamana Devi Barupal.